खंड १ नंबर ४ अक्तूबर २०१७

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर दिल्ली सम्मेलन

सुश्री प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, उद्घाटन भाषण देती हुईं।

हाल के वर्षों में दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) और त्रिकोणीय विकास सहयोग (टीडीसी) समस्त विकासशील देशों में आपसी सहभागिता के प्रमुख स्वरूपों के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इसके साथ ही आपसी सहभागिता की रूपरेखा और आयाम भी कई गुना बढ़ गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के आगाज के साथ ही इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है।

उभरते वैश्विक ढांचे की बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों पर विचार करने हेतु आरआईएस सभी हितधारकों को एकजुट करने में सबसे आगे रहा है। एसएससी पर चर्चा करने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए आरआईएस ने नई दिल्ली में 24–25 अगस्त 2017 को दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह हमारे द्वारा वर्ष 2013 में शुरू की गई श्रृंखला में तीसरा सम्मेलन था।

उद्घाटन सत्र का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और श्री यूरी अफानासीव, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक एवं भारत, नई दिल्ली में यूएनडीपी के निवासी प्रतिनिधि के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। आरआईएस के अध्यक्ष, राजदूत हरदीप एस पुरी ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री जॉर्ज शेदीक, दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर महासचिव के विशेष दूत एवं निदेशक, दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय, न्यूयॉर्क और प्रोफेसर ली जियाओयून, चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान नेटवर्क (सीआईडीआरएन), बीजिंग; अध्यक्ष, नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्स (नेस्ट) ने भी इस सत्र के दौरान अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली ने विशेष भाषण

पृष्ठ 12 पर जारी....

माननीय श्री मोहम्मद नशीद, पूर्व राष्ट्रपति, मालदीव गणराज्य समापन भाषण प्रस्तुत करते हुए।

एसडीजी एवं एकात्म मानववाद

डॉ. महेश शर्मा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति मंत्रालय और राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार संगोष्ठी में बोलते हुए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष मनाने हेतु विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली, नीति आयोग, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और दीनदयाल अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त रूप से 23–24 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में एसडीजी एवं एकात्म मानववाद पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री अतुल जैन, महासचिव, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के आरंभिक संबोधनों के साथ हुआ। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री राम माधव, निदेशक, इंडिया फाउंडेशन ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. महेश शर्मा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति मंत्रालय और राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबोधित किया।

श्री महेश चंद शर्मा, अध्यक्ष, एकात्म मानववाद के लिए अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन ने 'एसडीजी और एकात्म मानववाद – विकास के नए प्रतिमान के लिए गतिशील' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले दिन आयोजित पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। श्रीमती अर्चना चिटनिस, माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश सरकार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, माननीया सांसद (लोकसभा), पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार डॉ. अशोक टंडन और डॉ. रमेश के जालान, वैश्विक सलाहकार, अपशिष्ट प्रबंधन इस पैनल के सदस्यों में शामिल थे।

'सतत आर्थिक विकासः एसडीजी 8 और एसडीजी 12 के क्रियान्वयन' पर प्रथम सत्र की अध्यक्षता डॉ. बजरंग लाल गुप्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय ने की। श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। डॉ. वेंकटचलम अन्बुमोझी, आसियान एवं पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), इंडोनेशिया और प्रो. ए दामोदरन, आईपी प्रबंधन पर प्रोफेसर एवं आईपीआर चेयर (एमएचआरडी), आईआईएम बेंगलुरु इस पैनल के सदस्यों में शामिल थे। 'मानव एवं प्रकृति' के बीच सामंजस्य के लिए एसडीजी के बहुआयामी स्वरूप पर आयोजित द्वितीय सत्र की अध्यक्षता डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे माननीय सांसद (राज्य सभा) ने की थी। श्री अशोक जैन, सलाहकार (ग्रामीण विकास और एसडीजी), नीति आयोग, प्रो. टी सी जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, डॉ. लीना गुप्ता, सामाजिक वैज्ञानिक, डॉ. पी के आनंद, विजिटिंग फेलो, आरआईएस इस पैनल के सदस्यों में शामिल थे।

समापन दिवस की मुख्य थीम 'एसडीजी एवं एकात्म मानववादः आगे की राह' थी, जिसका शुभारंभ श्री अतुल जैन, महासचिव, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान के स्वागत भाषण के साथ हुआ। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ.विनय सहस्रबुद्धे, सांसद (राज्य सभा) ने प्रथम दिन के निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने गरिमापूर्ण समारोह को संबोधित किया।

श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने समापन भाषण दिया। माननीय डॉ. महेश शर्मा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति मंत्रालय और राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे और उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित भी किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन पर दीनदयाल अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष श्री वीरेंद्रजीत सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार संगोष्ठी में बोलते हुए।

विषमताएं कम करने पर राष्ट्रीय परामर्श

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया मुख्य भाषण देते हुए।

नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आरआईएस ने विशिष्ट एसडीजी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकारों, सीएसओ और अन्य सहित कई हितधारकों के साथ पिछले एक साल के दौरान अनेक राष्ट्रीय परामर्शों का आयोजन किया।

श्रृंखला के एक भाग के रूप में 28 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में विषमताओं के मुद्दों से जुड़े एसडीजी–10 पर एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया था।

डॉ. अशोक कुमार जैन, सलाहकार, नीति आयोग ने सभी का स्वागत किया और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने आरंभिक भाषण दिया। श्री यूरी अफानासीव, भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग ने विशेष भाषण दिया।

विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

एसडीजी के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून का शासन

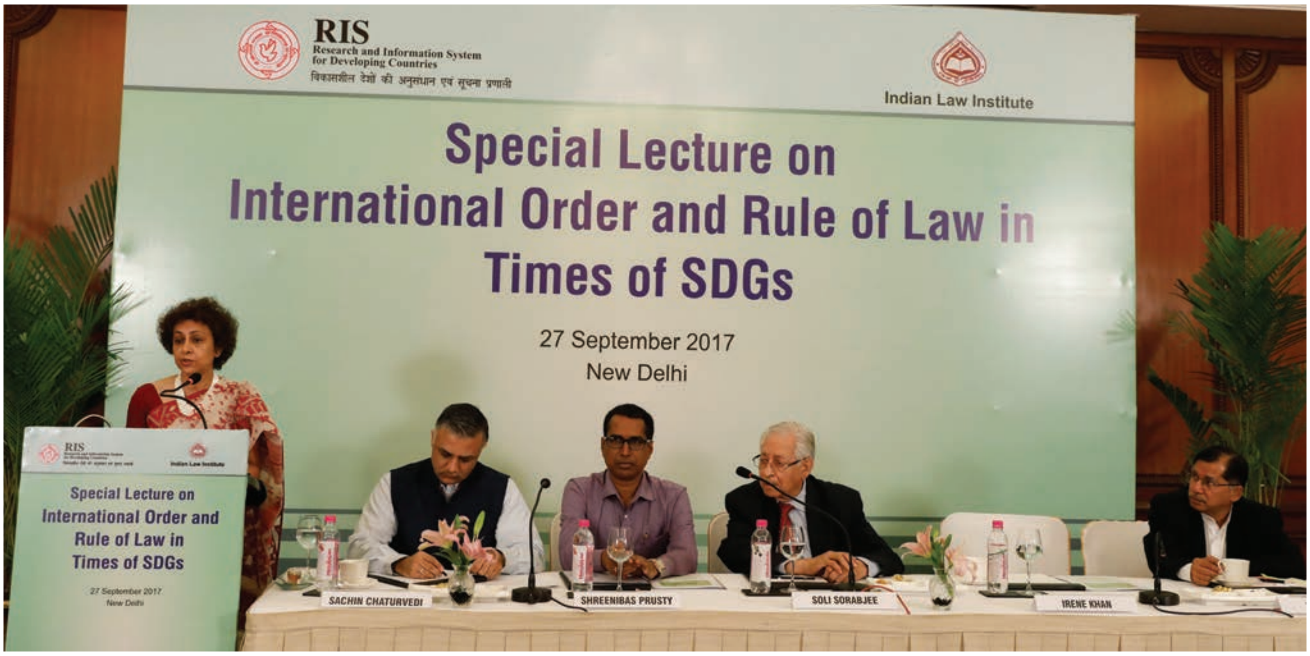

सुश्री आइरीन खान, महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय विकास कानून संगठन (आईडीएलओ) विशेष व्याख्यान देती हुई।

आरआईएस और भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) ने नई दिल्ली में 27 सितंबर, 2017 को 'एसडीजी के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून के शासन' पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ. श्रीनिबास प्रस्ती, रजिस्ट्रार, आईएलआई के आरंभिक संबोधनों के साथ हुआ। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल श्री सोली सोराबजी ने सत्र की अध्यक्षता की। सुश्री आइरीन खान, महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय विकास कानून संगठन (आईडीएलओ) ने 'एसडीजी के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून के शासन' पर विशेष व्याख्यान दिया। ज्ञानविषयक व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। विशेष व्याख्यान के अंत में प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोरः आगे की राह

'एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोरः आगे की राह' पर परामर्श का आयोजन 25 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में आरआईएस और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने परामर्श के दौरान एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) के कार्यकलाप कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप एस पुरी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने एएजीसी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।

माननीय श्री सिद्धार्थो आर. सूर्योदिपुरो, राजदूत नामित, इंडोनेशिया के दूतावास, प्रोफेसर डिरन मकिंदे, वरिष्ठ सलाहकार, एनईपीएडी औद्योगीकरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्र (एनआईएसटीआईएच), दक्षिण अफ्रीका और सीआईआई के महानिदेशक डॉ. चंद्रजीत बनर्जी ने भी अपने विचार पेश किए।

सुश्री रेनाना झाबवाला, राष्ट्रीय समन्वयक, चेयर, सेवा भारत स्व–नियोजित महिला संघ, सेवा रिसेप्शन सेंटर, डॉ. टी. पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, डॉ. हरप्रीत संधू, वैज्ञानिक (एफ) एवं प्रमुख, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद पैनल परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, सचिव, डीएचआर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू) तथा महानिदेशक, आईसीएमआर, प्रोफेसर मुस्ताफिजूर रहमान, प्रतिष्ठित फेलो, नीतिगत संवाद केंद्र, बांग्लादेश; डॉ. हन्निंग्टन ओडेम, कार्यकारी निदेशक, अफ्रीकी जैव–उद्यमिता केंद्र, लैविंग्टन, नैरोबी; प्रो. एलिजाबेथ सिडिरोपाउलस, निदेशक, दक्षिण अफ्रीकी अंतरराष्ट्रीय मामले संस्थान, दक्षिण अफ्रीका और डॉ. थॉमस फ्यूज, प्रमुख, प्रशिक्षण विभाग, जर्मन विकास संस्थान, बॉन, जर्मनी ने भाग लिया।

विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

सुश्री रुचिता बेरी, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद पैनल परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें डॉ. महाराज रसिगन, प्रोफेसर असाधारण, मूल्यांकन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान केंद्र, स्टेलनोबोश विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका, श्री सैदु नासिरु सुलेमान, नाइजीरिया; श्री जेम्स बिचाची वाफुला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनयिक अध्ययन, विदेश मंत्रालय, युगांडा, डॉ. फैनवेल केनाला बोकोसी, कार्यकारी निदेशक, ऋण एवं विकास पर अफ्रीकी फोरम और नेटवर्क, जिम्बाब्वे, डॉ. ए.के. कृष्ण कुमार, प्रधान सलाहकार, आईएल एंड एफएस क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिमिटेड और श्री गेविन मैकगिलिवरे, प्रमुख, डीएफआईडी कार्यालय, भारत ने भाग लिया। एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

एएजीसी पर परामर्श बैठक

एएजीसी विजन दस्तावेज पर आगे चर्चा करने के लिए आरआईएस ने ईआरआईए और आईडीई–जेट्रो के साथ मिलकर संयुक्त रूप से टोक्यो में 30 अगस्त 2017 को एक परामर्श बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आरआईएस की टीम में ये शामिल थेः प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, डॉ. हरप्रीत संधू, आईसीएमआर, सुश्री रुचिता बेरी, आईडीएसए, डॉ. सौम्या चट्टोपाध्याय, एडीबी, प्रोफेसर डॉ. सेल्वा कुमार, तमिल विश्वविद्यालय, प्रो. संतोष मेहरोत्रा, जेएनयू, डॉ. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, प्रो. टी. सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो और डॉ. प्रियदर्शी दाश, रिसर्च एसोसिएट।

एएजीसी और ट्यूनिशिया की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं

जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, अहमदाबाद में 22–25 मई, 2017 को अफ्रीकी विकास बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) पर एक विजन दस्तावेज जारी किया गया था। आरआईएस ने अन्य संस्थानों के साथ मिलकर एएजीसी पर एक प्रमुख अनुसंधान कार्यकलाप कार्यक्रम शुरू किया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य उन परियोजनाओं के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाना है जो इस विकास गलियारे की सफलता में योगदान करेंगी।

एएजीसी के संवादात्मक सत्र में अनेक प्रतिभागी शिरकत करते हुए।

आरआईएस ने ट्यूनिशिया गणराज्य के दूतावास के राजदूत माननीय श्री नेजमेद्दीन लाखल को आमंत्रित किया। उन्हें आरआईएस में 6 जुलाई 2017 को 'एएजीसी और ट्यूनिशिया की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं' पर आयोजित प्रथम संवादात्मक परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप एस. पुरी ने संवादात्मक सत्र की अध्यक्षता की। श्री अमर सिन्हा, पूर्व सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रतिभागियों में भारत स्थित अफ्रीकी मिशनों, विभिन्न शैक्षणिक, व्यावसायिक और औद्योगिक हलकों के प्रतिनिधि शामिल थे।

एएजीसी पर उद्योग परामर्श

आरआईएस में आयोजित एएजीसी परामर्श बैठक में अनेक प्रतिभागी शिरकत करते हुए।

आरआईएस और भारतीय उद्योग परिसंघ ने 18 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) पर एक उद्योग परामर्श का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप एस. पुरी के आरंभिक संबोधन के साथ हुआ। प्रो.सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने एएजीसी पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद श्री एस. कुप्पुस्वामी, सलाहकार–समूह वित्त एवं विशेष परियोजनाएं, शपूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इसे संबोधित किया।

खुली परिचर्चा में मुख्य विषय ये थे: बुनियादी ढांचा, कृषि, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल। इसमें प्रमुख वक्ता ये थे: श्री मनोज कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और श्री अजनीश कुमार, उप महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद। श्री प्रणव कुमार, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, सीआईआई ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) विजन दस्तावेज को अहमदाबाद में मई 2017 में आयोजित अफ्रीकी विकास बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान जारी किया गया था। सितंबर 2017 में जापान के माननीय प्रधानमंत्री श्री शिंजो अबे की आगामी भारत यात्रा को ध्यान में रखते हुए विजन दस्तावेज में परिकल्पित कार्य योजना और भी ज्यादा अहम नजर आती थी। आरआईएस अन्य संस्थानों अर्थात, आईडीई–जेट्रो और ईआरआईए के साथ मिलकर विजन दस्तावेज पर निरंतर आगे काम कर रहा है।

'आसियान–भारत संबंधों' पर दिल्ली संवाद 9

भारत सरकार की माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 'दिल्ली संवाद 9' के दौरान आसियान देशों के अन्य गणमान्य आतिथियों के साथ।

भारत सरकार की माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 4–5 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में 'आसियान–भारत संबंध: अगले 25 वर्षों के लिए सही दिशा तय करने' पर आयोजित दो दिवसीय 'दिल्ली संवाद 9' का शुभारंभ किया। इस संवाद का आयोजन नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। आरआईएस स्थित एआईसी इस आयोजन का एक प्रमुख भागीदार था। इस सत्र में उपस्थित प्रमुख लोगों में राजनीतिक नेतागण, नीति निर्माता, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत की हस्तियां, प्रबुद्ध मंडल या विशेषज्ञ समूह (थिंक टैंक), भारत एवं आसियान के शिक्षाविद शामिल थे। इस अवसर पर प्रमुख गणमान्य व्यक्ति ये थे: जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह, माननीय विदेश राज्य मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री, माननीय श्री फाम बिन्ह मिन्ह, उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री, वियतनाम, माननीय यू क्याव टिंट स्वे, केंद्रीय मंत्री, राज्य काउंसलर के कार्यालय का मंत्रालय, म्यांमार और माननीय हिरुबलन वी पी, आसियान राजनीतिक–सुरक्षा समुदाय विभाग के उप महासचिव, आसियान सचिवालय।

आसियान–भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर जारी बहस को आगे बढ़ाने के लिए 'दिल्ली संवाद 9' को मोटे तौर पर तीन सत्रों अर्थात मंत्रिस्तरीय सत्र, कारोबारी सत्र और अकादमिक सत्र में विभाजित किया गया था। इस आयोजन के दौरान कुछ पैनल परिचर्चाएं इन विषयों पर आयोजित की गई थीं: 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रुझान और भारत एवं आसियान पर उसका असर', 'भारत–आसियान व्यापार संबंध', 'भारत–आसियान भागीदारी: एसएमई और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय नेटवर्क का निर्माण करना', 'भारत–आसियान बुनियादी ढांचागत निवेश: वर्तमान परिदृश्य एवं आगे की राह', 'कनेक्टिविटी के जरिए व्यापार एवं पर्यटन – फोकस पूर्वोत्तर एवं पूर्वी भारत', 'क्षेत्रीय भू–राजनीति: एशिया–प्रशांत क्षेत्र में सत्ता की सरगर्म राजनीति', 'एशिया–प्रशांत क्षेत्र में नए कनेक्टिविटी प्रतिमान', 'प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं बृहत डेटा', और 'सामाजिक–सांस्कृतिक सहभागिता एवं प्रवासियों से जुड़ाव'।

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में नए कनेक्टिविटी प्रतिमानों पर आयोजित पैनल परिचर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने कई आसियान देशों के साथ भारत की मौजूदा कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर एक प्रस्तुति दी। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप एस पुरी ने संस्कृति एवं सभ्यता संबंधी जुड़ाव पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।

आसियान के स्थायी प्रतिनिधियों का दौरा

स्थायी प्रतिनिधियों की आसियान समिति ने 7 जुलाई 2017 को आरआईएस स्थित एआईसी का दौरा किया। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप सिंह पुरी ने भू–राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे गतिशील परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आसियान–भारत रणनीतिक साझेदारी की अहमियत पर एक प्रस्तुति दी। आसियान के राजनयिक ने राजदूत पुरी के साथ सकारात्मक बातचीत की। डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

आसियान सीपीआर के साथ राजदूत हरदीप सिंह पुरी और राजदूत सुरेश रेड्डी।

आसियान–भारत संवाद संबंधों की 25वीं वर्षगांठ

आसियान के अनेक प्रतिनिधियों के साथ हैं ग्रैंड फिनाले प्रतियोगी।

रॉयल थाई दूतावास ने आसियान नई दिल्ली समिति और आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र के सहयोग से 1 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली स्थित आर्य सभागार में 'द आसियान क्विज' का आयोजन किया। इस अवसर पर आसियान की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और आसियान–भारत संवाद संबंधों की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया गया। इसका उद्देश्य भारत की जनता, विशेष रूप से भारतीय युवाओं के बीच आसियान एवं इसकी उपलब्धियों के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिससे इस संगठन एवं इसके सदस्य देशों, उनकी जनता और पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत के साथ उनके पारस्परिक संवादों के बारे में अधिक समझदारी विकसित होगी। दिल्ली–एनसीआर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों की कुल 150 टीमों ने इस प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, जो आसियान पर केंद्रित था।

भारत में थाईलैंड साम्राज्य के राजदूत एवं आसियान नई दिल्ली समिति के वर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री चुटिंतॉर्न गोंगसाकडी ने भव्य समापन (ग्रैंड फिनाले) से पहले मुख्य भाषण दिया। रॉयल थाई दूतावास के मिशन के उप प्रमुख एवं मंत्री श्री अपिरत सुगोंधाभिरोम ने विशेष धन्यवाद ज्ञापन किया जिन्होंने आसियान प्रश्नोत्तरी को बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए आसियान नई दिल्ली समिति और आसियान–भारत केंद्र के साथ–साथ इसके प्रतिभागियों का भी धन्यवाद किया। एआईसी के डॉ. दुरइराज कुमारसामी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

आसियान के पत्रकारों का आगमन

आसियान देशों के 20 पत्रकारों के एक समूह का आगमन 4 जुलाई 2017 को आरआईएस स्थित एआईसी में हुआ। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने आरंभिक भाषण दिया। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप सिंह पुरी ने आसियान–भारत रणनीतिक साझेदारी और भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम का संक्षिप्त ब्योरा पेश किया। एआईसी की गतिविधियों अथवा कार्यकलापों से भी इन पत्रकारों को अवगत कराया गया। राजदूत पुरी ने इन पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

आसियान पत्रकार आरआईएस संकाय के साथ।

भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय संबंध

भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय संबंधों पर आयोजित संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित हैं अनेक प्रतिभागी।

आरआईएस, नई दिल्ली स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय, बैंकाक स्थित आसियान अध्ययन केंद्र और भारतीय अध्ययन केंद्र ने मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज (मकायास), कोलकाता तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं विकास अध्ययन केंद्र (सीएसआईआरडी), कोलकाता के सहयोग से 6–7 सितंबर, 2017 को कोलकाता के मकायास में 'भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय संबंधः एक मजबूत आसियान–भारत भागीदारी की ओर' विषय पर एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

डॉ. बिनोदा मिश्रा, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं विकास अध्ययन केंद्र (सीएसआईआरडी), कोलकाता ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। आरआईएस, नई दिल्ली स्थित एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने आरंभिक भाषण दिया। प्रो. सुथिफंद चिराथीवत, कार्यकारी निदेशक, आसियान अध्ययन केन्द्र, चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय, बैंकाक ने उद्घाटन भाषण दिया। राजदूत राजीव भाटिया, विशिष्ट फेलो, गेटवे हाउस, मुंबई और म्यांमार में भारत के पूर्व राजदूत ने विशेष भाषण दिया।

कार्यशाला के उद्देश्य ये थेः (1) आसियान–भारत साझेदारी के संदर्भ में भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय संबंध जिन चुनौतियों का सामना करता रहा है उनकी पहचान करना, (2) त्रिपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए शुरू की जाने वाली रणनीतियों एवं नीतियों को प्रस्तुत करना और (3) नीति निर्माताओं के ध्यानार्थ लाने के लिए अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रकाशित करना।

इस कार्यशाला में 25 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें शैक्षणिक शोधकर्ता, सरकारी अधिकारी और विदेशी अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यशाला के दौरान सात सत्र आयोजित किए गए थे जिनमें एक आरंभिक सत्र के साथ–साथ त्रिपक्षीय सहयोग की गतिशीलता, विदेश नीति एवं सुरक्षा मुद्दों; सांस्कृतिक संपर्कों, व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर फोकस करने वाले एक–एक सत्र भी शामिल थे। कार्यशाला का उद्देश्य नये आयामों और विचारों के संदर्भ में भारत, म्यांमार एवं थाईलैंड के अनुभवों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करना था, जिससे त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक क्रियान्वयन योग्य नीतिगत एजेंडा तैयार करने में मदद मिलेगी। समापन का समय नजदीक आने पर प्रो. सुथिफंद चिराथीवत, आसियान अध्ययन केन्द्र, चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय, बैंकाक और डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने कार्यवाही का सार प्रस्तुत किया। समापन भाषण प्रो. जे के रे, राष्ट्रीय प्रोफेसर, कोलकाता द्वारा दिया गया था। अंत में, कोलकाता स्थित सीएसआईआरडी की सीनियर फेलो डॉ. अर्पिता बसु रॉय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रो. समन केलेगामा को श्रद्धांजलि

बैठक में उपस्थित हैं (बाएं से) डॉ. नागेश कुमार, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. दीपक नैय्यर, माननीया श्रीमती चित्रांगनी वागीसवारा और प्रो. मुचकुंद दुबे।

आरआईएस ने प्रो. समन केलेगामा, कार्यकारी निदेशक, कोलम्बो स्थित, इन्सटिटयूट ऑफ पोलिसी स्टडीज़ (आईपीएस) को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 11 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में उनके अहम योगदान को स्मरण किया गया।

श्रीलंका की उच्चायुक्त माननीया श्रीमती चित्रांगनी वागीसवारा ने भी इस अवसर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। डॉ. नागेश कुमार, निदेशक, सामाजिक विकास प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र–एस्कैप, प्रो. दीपक नैय्यर, अर्थशास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर, जेएनयू एवं सह–अध्यक्ष, एसएसीईपीएस, प्रो. मुचकुंद दुबे, अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण की दिशा में प्रो. समन केलेगामा के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम का प्रथम व्याख्यान

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. आर. चिदंबरम व्याख्यान देते हुए।

'मेक इन इंडिया', 'कौशल भारत', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्टार्ट–अप इंडिया' सरकार की कुछ ऐसी नई पहल हैं जिनका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का व्यापक एवं बेहतरीन इस्तेमाल करना है। सरकार और राजनीतिक नेतृत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोगी फायदों से अलग–अलग क्षेत्रों जैसे कि उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की गति तेज करने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों, उद्योग, सरकार और अन्य नीति–निर्माता निकायों सहित राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली की क्षमता बढ़ाना अत्यंत जरूरी है जिसमें अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थान भी शामिल हैं।

आरआईएस भी विज्ञान–समाज के आपसी जुड़ाव (कनेक्ट) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने भारत पर्यावास केंद्र यानी इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे अन्य संस्थानों के सहयोग से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम लांच किया है। अन्य साझेदार संस्थान ये हैं– ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी), विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई), उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत–फ्रांस केंद्र (आईएफसीपीएआर/सीईएफआईपीआरए) और विज्ञान प्रसार।

यह फोरम विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति के विभिन्न पहलुओं पर बहस को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है। यही नहीं, फोरम ने एक 'मासिक व्याख्यान श्रृंखला' की योजना बनाई है, ताकि वह पारस्परिक बातचीत या संवाद के लिए एक व्यापक सार्वजनिक मंच (प्लेटफॉर्म) के रूप में स्वयं को स्थापित कर सके। यह फोरम एसएंडटी के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न सकारात्मक घटनाक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ–साथ एसएंडटी तथा नवाचार से समाज को अपेक्षाओं और उम्मीदों पर बहस में तेजी लाकर विज्ञान एवं समाज के बीच की खाई को भी पाटेगा। मासिक व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार संस्थान किसी प्रसिद्ध विशेषज्ञ के व्याख्यान का आयोजन करने के लिए भी अपनी ओर से ठोस पहल करेगा।

एसटीआईपी फोरम व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान आरआईएस और भारत पर्यावास केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 26 सितंबर 2017 को आयोजित किया गया था।

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. आर. चिदंबरम ने व्याख्यान दिया और 'सतत विकासः विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका' पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, श्री राकेश कैकर, निदेशक, आईएचसी, डॉ. मुकेश कुमार, निदेशक, आईएफसीपीएआर/सीईएफआईपीआरए और डॉ. विभा धवन, विशिष्ट फेलो एवं वरिष्ठ निदेशक, टेरी ने भी एसटीआईपी फोरम की अहमियत और भूमिका के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए।

(एसटीआईपी) फोरम की व्याख्यान माला

- 30 vDVcj 2017% सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं टाटा मोटर्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. वी सुमंत्रन 'गतिशीलता के पहलुओं' पर अपने विचार पेश करेंगे।
- 30 uocj 2017 % पूर्व भारतीय राजनयिक डॉ. भास्कर बालाकृष्णन। विषयः 'प्रौद्योगिकी और भारतीय विदेश नीतिः रुझान एवं अवसर'। डॉ. आर. चिदंबरम, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार और अध्यक्ष, कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति इस अवसर पर अध्यक्षता करेंगे।
- 21 fnlcj 2017% डॉ. फ्रैंक शू, यूसी बर्कले एवं राष्ट्रीय सिंघुआ विश्वविद्यालय, ताइवान के विख्यात तारा–भौतिकविद्। विषयः 'तरल–नमक प्रौद्योगिकियों से जलवायु परिवर्तन पर नियन्त्रण।

एजेंडा 2030 में वैश्विक भागीदारी की भूमिका

'एजेंडा 2030 में: वैश्विक भागीदारी की भूमिका' विषय पर एक पैनल परिचर्चा आरआईएस और संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन, न्यूयॉर्क द्वारा संयुक्त रूप से 18 जुलाई, 2017 को आयोजित की गई थी।

एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन पर आयोजित पैनल परिचर्चा में मौजूद प्रतिभागी।

इस बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को लागू करने के लिए आवश्यक साधनों के साथ–साथ एसडीजी के स्थानीयकरण और एसडीजी के कार्यान्वयन में दक्षिणी अर्थात विकासशील देशों के संस्थानों की भूमिका का भी आकलन किया गया। बैठक में इन मसलों पर चर्चाएं की गईं कि विभिन्न स्त्रोतों यथा सार्वजनिक, निजी, अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू स्त्रोतों से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के लिए वित्तपोषण के जरिए कार्यान्वयन के विशाल वैश्विक साधनों को कैसे वितरित किया जाए, कारोबार में नवाचार का दोहन करने के लिए नए गठबंधन करने की क्या गुंजाइश है, प्रौद्योगिकी तक पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए और एजेंडे को लागू करने के लिए उभरते विकासशील देशों द्वारा उठाए गए कदमों को समायोजित करने हेतु संस्थागत रूपरेखा कैसे विकसित की जाए।

इस परिचर्चा के दौरान एसडीजी के स्थानीयकरण के अलावा एसडीजी की प्राप्ति के लिए वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान बढ़ाने पर भी विचार–विमर्श किया गया। इस दौरान ये विषय थे: (1) संस्थागत रूपरेखा एवं उभरते विकासशील देशों का अभ्युदय (2) एसडीजी का स्थानीयकरण (3) विकास के लिए वित्तपोषण एवं दक्षिणी यानी विकासशील देशों के संस्थानों की भूमिका (4) भारत का देश संबंधी परिप्रेक्ष्य।

आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप एस. पुरी ने इस चर्चा की अध्यक्षता की। सुश्री मिन्ह–थू फाम, नीति के लिए कार्यकारी निदेशक, संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा संक्षिप्त आरंभिक भाषण दिए। प्रोफेसर रहमान सोभान, अध्यक्ष, नीतिगत संवाद केंद्र, बांग्लादेश, श्री जितेंद्र शंकर माथुर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, श्री मैनुअल एफ. मोंटेस, वित्त एवं विकास पर वरिष्ठ सलाहकार, जिनेवा स्थित दक्षिण केंद्र, श्री यूरी अफानासीव, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक, सुश्री रोमिली ग्रीनहिल, सीनियर रिसर्च फेलो, प्रवासी विकास संस्थान इस पैनल के सदस्यों में शामिल थे। सत्र का समापन सुश्री मिन्ह–थू फाम और प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने किया।

दक्षिण–दक्षिण वैश्विक विचारक पहल

दक्षिण–दक्षिण वैश्विक विचारक पहल पर एक विशेष कार्यक्रम, यूएनडीपी एवं नेस्ट के बीच सहमति–पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए प्रभाव आकलन पर कार्यशाला का आयोजन 14 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में किया गया। सुश्री सिमोना मैरिन्स्कू, निदेशक, विकास प्रभाव समूह, ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट, यूएनडीपी ने हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। श्री मैग्डी मार्टिनेज–सोलिमन, सहायक महासचिव एवं निदेशक, ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट, यूएनडीपी ने सभी का स्वागत किया और आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप एस. पुरी ने उद्घाटन भाषण दिया।

पृष्ठ 12 पर जारी....

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए प्रभाव आकलन' पर आयोजित कार्यशाला प्रगति पर है।

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के प्रयास

आरआईएस में 6 जुलाई 2017 को 'कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के प्रयास' पर एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत हरदीप एस. पुरी ने परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. अरविंद गुप्ता, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने विशेष भाषण दिया। श्री रजत नाग, विशिष्ट फेलो, एनसीएईआर ने विशेष भाषण दिया, जिसके बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई।

परामर्श बैठक में उपस्थित हैं अनेक प्रतिभागी।

बैठक के एजेंडे में इन सभी के द्वारा विषयगत परिचर्चाएं शामिल थीं: प्रो.सचिन चतुर्वेदी: एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर, डॉ. विजय सखुजा, एनएमएफ: हिंद महासागर और समुद्री कनेक्टीविटी, डॉ. प्रीतम बनर्जी, डीएचएल इंडिया: सार्क, बीबीआईएन एवं उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर, डॉ. प्रबीर डे, आरआईएस: आसियान–भारत कनेक्टिविटी, बिम्सटेक कॉरिडोर एवं बीसीआईएम आर्थिक कॉरिडोर और डॉ. राजीव रंजन चतुर्वेदी, आईएसएएस–एनयूएस: बेल्ट एवं रोड पहल। श्री रविंद्रन, एसएईए ग्रुप रिसर्च, सिंगापुर और श्री दिपंजन रॉय चौधरी, इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली इस पैनल के सदस्यों में शामिल थे।

व्लादिमीर याकुनिन का आरआईएस में आगमन

आरआईएस ने भारत–रूस द्विपक्षीय संबंधों के 70 वर्षों का जश्न मनाने के एक हिस्से के रूप में 'वैश्विक संदर्भ में भारत–रूस द्विपक्षीय संबंधों' पर 28 जुलाई 2017 को एक परिचर्चा बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। आरआईएस की अनुसंधान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष राजदूत एस. टी. देवारे ने सत्र की अध्यक्षता की। सभ्यता अनुसंधान संस्थान के संवाद के पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष एवं मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान संकाय के राष्ट्र राजनीति विभाग के प्रमुख प्रोफेसर व्लादिमीर याकुनिन ने विशेष भाषण दिया। इसके बाद अनुराधा चेनॉय, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और श्रीमती एकातेरिना सेमेनोवा, प्रथम सचिव, रूसी संघ का दूतावास द्वारा पैनल परिचर्चा हुई।

भारत–रूस द्विपक्षीय संबंधों पर आयोजित परिचर्चा बैठक में उपस्थित हैं अनेक प्रतिभागी।

आरआईएस में अन्य प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया गया

- समकालीन भारत और इसकी विरासत के बारे में विभिन्न देशों के बीच जागरूकता एवं समझ बढ़ाने के लिए बाह्य प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग के पहुंच (आउटरीच) कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में भारत–आसियान मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत आसियान देशों के तकरीबन 20 पत्रकारों ने 4 जुलाई 2017 को आरआईएस का दौरा किया।
- 10 थाई युवा छात्रों के एक समूह ने 11 अगस्त 2017 को आरआईएस का दौरा किया। वे 'भारत शिक्षा यात्रा कार्यक्रम' के एक भाग के रूप में भारत आए थे।
- श्रीलंका के 15 पत्रकारों/संपादकों के एक समूह ने विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग के परिचितीकरण कार्यक्रम के तहत 19 सितंबर 2017 को आरआईएस का दौरा किया।

'उभरने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के व्यापार से लाभ उठाना: ब्रिक्स अनुभव'

डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस द्वारा 4 जुलाई 2017 को 'उभरने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के व्यापार से लाभ उठाना: ब्रिक्स अनुभव' विषय पर एक ब्रेकफास्ट सेमिनार आरआईएस में आयोजित किया गया था। प्रो. विजय कुमार कौल, डीन, अप्लायड सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस सेमिनार की अध्यक्षता की।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग और त्रिकोणीय विकास सहयोग...
....पृष्ठ 1 से जारी

दिया। सुश्री प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया। माननीय श्री मोहम्मद नशीद, पूर्व राष्ट्रपति, मालदीव गणराज्य ने समापन भाषण दिया। सम्मेलन का विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग और त्रिकोणीय विकास सहयोग के समस्त प्रतिभागी।

दक्षिण–दक्षिण वैश्विक....
....पृष्ठ 10 से जारी

यूएनडीपी और आरआईएस के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। श्री जॉर्ज शेदीक, दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के दूत एवं दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक और राजदूत तन्मय लाल, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि ने बधाई भाषण दिए।

एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद एसएससी वैश्विक विचारक कार्यशाला – एसएससी के लिए प्रभाव आकलन किया गया। सुश्री जिआओजुन ग्रेस वांग, उप निदेशक, दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इस अवसर पर संचालिका थीं।

डॉ. निस्सान एलेसैंड्रो बेशारती, सीनियर रिसर्च फेलो/विजिटिंग प्रोफेसर/एमएंडई स्पेशलिस्ट, अफ्रीकी समन्वयक, नेस्ट अफ्रीका, डॉ. पॉउलो एस्टेवेस, ब्रिक्स नीतिगत केंद्र के पर्यवेक्षक, नेस्ट ब्राजील, डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस इस अवसर पर मुख्य वक्ता थे। श्री यूरी अफानासीव, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक एवं भारत में यूएनडीपी के निवासी प्रतिनिधि ने विशेष भाषण दिए। इसके बाद सुश्री सिमोना मैरिन्स्कू, निदेशक, विकास प्रभाव समूह, ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट ने समापन भाषण दिया।

बदलता भारतः गरीबी का उन्मूलन करना, समृद्धि को बढ़ावा देना

आरआईएस ने नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर 17 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 'बदलता भारतः गरीबी का उन्मूलन करना, समृद्धि को बढ़ावा देना' विषय पर पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। प्रो. अरविंद पनगढिया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, प्रो. जगदीश भगवती, कोलंबिया विश्वविद्यालय, राजदूत हरदीप एस. पुरी, अध्यक्ष, आरआईएस, प्रो. टी.सी.ए. अनंत, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् एवं सचिव, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार, श्री अनुपम खेर, महिला–पुरुष समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र के राजदूत, और राजदूत सैयद अकबरुद्दीन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इस पैनल के प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक थे।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- 3 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास द्वारा नॉर्वे के राजदूत के साथ आयोजित संवादात्मक सत्र में भाग लिया।
- ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा 7 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के साथ व्यापक आर्थिक अवलोकन पर आयोजित गोलमेज परिचर्चा में भाग लिया।
- 21 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा आयोजित न्यासी बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
- 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 'वैश्विक आर्थिक गवर्नेंसः अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और भारत' पर आयोजित विचार–मंथन सत्र में भाग लिया।
- 31 जुलाई 2017 को टोक्यो में जेट्रो द्वारा आयोजित ट्रैक 1.5 की बैठक में एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर पर एक प्रस्तुति दी।
- भारत की विकास सहयोग नीति के साथ–साथ एशिया और अफ्रीका में जापान की सहभागिता की विस्तृत संरचना, स्वरूप एवं रूपरेखाओं के बारे में चर्चा करने के लिए 1 अगस्त 2017 को टोक्यो स्थित जेआईसीए संस्थान में आयोजित गोलमेज बैठक में भाग लिया।
- 3 अगस्त 2017 को सिंगापुर में दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान (आईएसएएस) द्वारा 'व्यापार एवं आर्थिक एकीकरणः दक्षिण एशिया, दक्षिण–पूर्व एशिया और एशिया–प्रशांत' पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य भाषण दिया।
- 22 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 'विकास सहयोग का क्या भविष्य है? अभिनव और समावेशी दक्षिण–दक्षिण संस्थानों का निर्माण करना' विषय पर आयोजित संवादात्मक सत्र में भाग लिया।
- 31 अगस्त 2017 को बांडुंग में इंडोनेशिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा 'एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी): हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के लिए निहितार्थ' पर आयोजित बैठक में 'एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी): हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग (आईओआरसी) के लिए निहितार्थ' पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 सितंबर 2017 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में '2030 एजेंडे को हासिल करने के लिए दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग, अभिनव एवं समावेशी भागीदारी का निर्माण करना' विषय पर आयोजित डीसीएफ कार्यशाला में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग– बीएपीए के बाद चालीस वर्ष : चुनौतियां और अवसर' पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवादात्मक बैठक में 'एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी)' पर एक प्रस्तुति दी।
- 14 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में जापान विदेश व्यापार संगठन (जेट्रो) द्वारा आयोजित भारत–जापान आर्थिक फोरम की बैठक के दौरान 'एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी): एएजीसी विजन रिपोर्ट और भारत–जापान सहयोग एवं गठबंधन' पर आयोजित सत्र में 'एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी)' पर एक प्रस्तुति दी।
- 17 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) द्वारा 'विकास के लिए अनुसंधान परिदृश्य' विषय पर आयोजित अनौपचारिक परिचर्चा में भाग लिया।
- 21 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में शांति के लिए विश्वविद्यालय, कोस्टा रिका के दूतावास द्वारा 'शांति के लिए एक साथः सभी के लिए गरिमा, सुरक्षा और सम्मान' विषय पर आयोजित 'शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस' पर भाषण दिया।
- 21 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में चीनी जनवादी गणराज्य के दूतावास द्वारा 'डोंग लैंग के पश्चात : चीन–भारत संबंधों की भावी दिशा' विषय पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

प्रो. एस. के. मोहंती

- 21 जुलाई 2017 को चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा आयोजित 'आम तौर पर ट्रेडिंग की जाने वाली वस्तुओं पर (दूसरी पुनर्गठित) विशेषज्ञ समिति (एनटीएसी पर ईसी)' की तेरहवीं बैठक में भाग लिया।
- 1 अगस्त 2017 को बाली में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और व्यापार मंत्रालय, इंडोनेशिया द्वारा 'व्यापार एवं निवेश पर व्यावहारिक कार्यकलाप (वर्कस्ट्रीम) और आईओआरए आर्थिक एकीकरण' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
- 1 अगस्त 2017 को बाली में 'व्यापार एवं निवेश पर व्यावहारिक कार्यकलाप (वर्कस्ट्रीम) और आईओआरए आर्थिक एकीकरण' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में संसाधन वक्ता के तौर पर भाग लिया और इसके साथ ही व्यापार एवं निवेश पर व्यावहारिक कार्यकलाप संबंधी अनुशंसाओं, जो आईओआरए आर्थिक एकीकरण में योगदान देंगी, पर आयोजित सत्र में 'एक गतिशील आर्थिक समूह के रूप में आईओआरए का उद्भवः नीतिगत कदमों के लिए रणनीतियां विकसित करना' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 2–3 अगस्त 2017 को बाली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और इंडोनेशिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (सीएसओ) की सातवीं द्विवार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।
- 4 अगस्त 2017 को इंडोनेशिया के बोगोर में विदेश मंत्रालय, नीतिगत विश्लेषण एवं विकास एजेंसी द्वारा 'आईओआरए आर्थिक एकीकरण' पर विशेषज्ञों के साथ आयोजित फोकस समूह परिचर्चा (एफजीडी) में भाग लिया और 'आईओआरएः एक अप्रयुक्त गतिशील आर्थिक समूह' पर प्रस्तुति दी।
- 11 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर पर आयोजित बैठक में भाग लिया और 'एशिया

अफ्रीका विकास कॉरिडोर विजन रूपरेखाः अवधारणा से ठोस कदम की ओर अग्रसर' पर एक प्रस्तुति दी।

- 11 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया और भारत गणराज्य एवं मॉरीशस गणराज्य के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर एक प्रस्तुति दी।
- 12 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में 'सेवा क्षेत्रः भारत–मॉरीशस जेएसजी' पर वाणिज्य विभाग के व्यापार नीति प्रभाग में आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 27–28 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के लिए संयुक्त अध्ययन समूह की रिपोर्ट पर परिचर्चा हेतु आयोजित आधिकारिक संवाद में भाग लिया और मॉरीशस सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 21 जुलाई 2017 को सीएसआईआर–एचआरडीसी द्वारा वैज्ञानिकों के लिए आयोजित 34वें प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'आईपीआर के मूल सिद्धांतों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में नैतिकता तथा मूल्यों' पर व्याख्यान दिए।
- 4 अगस्त 2017 को सावित्रीभाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा 'नए भारत के लिए आयुष अनुसंधानः विजन और रणनीतियां' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। इसके साथ ही 'सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण' पर आयोजित विशेष सत्र में भी योगदान दिया।
- 5 सितंबर 2017 को एनआरडीसी द्वारा अफ्रीकी देशों के लिए 'बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण एवं सहयोग और भारत–अफ्रीका विकास साझेदारी' पर आयोजित भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में 'आईपीआरः नीति के अवलोकन और विकासशील देशों के लिए चुनौतियां' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 15 सितंबर 2017 को दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त फिक्की–आईपीओ कार्यक्रम के दौरान 'भारत में आईपी परितंत्रः आगे की राह' पर व्याख्यान दिया।
- 18 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में डीएचजेएस के अधिकारियों के लिए आयोजित अनुकूलन पाठ्यक्रम में 'आईपीआर न्यायशास्त्र – वर्तमान अधिनिर्णयन में गुंजाइश एवं प्रासंगिकता, आईआरपी कानूनी व्यवस्था का उद्भव एवं विकास, संवैधानिक अनिवार्यताओं और वैधानिक एवं न्यायिक प्रतिक्रियाओं' पर आयोजित दो सत्रों को संबोधित किया।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा गठित आईपीआर चेयर समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में योगदान दिया।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फेलो

- 11–13 सितंबर 2017 के दौरान मलेशिया के कुआलालम्पुर में 'एशिया–प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ खाद्य प्रणालियों और पोषण में कृषि जैव प्रौद्योगिकियों' पर आयोजित क्षेत्रीय बैठक में 12 सितंबर को 'एशिया–प्रशांत क्षेत्र में कृषि जैव प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, क्षमता और अनुकूल माहौल की स्थितिः कुछ प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रतिपादन' पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. बीना पांडे

रिसर्च एसोसिएट

- 26 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में अल्यूमनीपोर्टल ड्यूशलैंड और जीआईजेड इन द्वारा आयोजित 'शिक्षा के बिना कोई भविष्य नहीं' लैब में एक इनपुट स्पीकर के रूप में 'सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में आईएलओ द्वारा आयोजित 'प्रवासन एवं गतिशीलता पर यूरोपीय संघ– भारत संवाद' में भाग लिया।

डॉ. प्रियदर्शी दाश

रिसर्च एसोसिएट

- 20 जुलाई, 2017 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 'बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में निवेश को शामिल करने' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 10 अगस्त, 2017 को उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के एमए (विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक अर्थशास्त्र) के छात्रों को 'वैश्विक एवं क्षेत्रीय व्यापार और वित्त में हालिया रुझानों' पर प्रस्तुति दी।
- 20 सितंबर 2017 को मास्को स्थित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं लोक प्रशासन की रूसी राष्ट्रपति अकादमी में 'जी20 और ब्रिक्सः लचीले एवं संतुलित विकास के लिए सहयोग' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'ब्रिक्स का अभ्युदय, उभरते बाजारों और वैश्विक गवर्नेंस में उभरते प्रतिपादन' पर प्रस्तुति दी।
- 25 सितंबर, 2017 को कजाकस्तान के अल्माटी में 'उभरती वैश्विक शक्तियों के रूप में भारत और चीनः मध्य एशिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'कॉरिडोर के अर्थशास्त्र की व्यापक प्रासंगिकताः एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर का एक उदाहरण' विषय पर ऑनलाइन प्रस्तुति दी।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 3–4 अगस्त 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, नया रायपुर में 'एसडीजी और प्रशासनिक सुधारों' पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान 'भारत में नीतिगत रूपरेखा और एसडीजी के तहत समीक्षा' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. दुरइराज कुमारसामी

आरआईएस स्थित एआईसी में सलाहकार

- आरआईएस स्थित एआईसी में सलाहकार डॉ. दुरइराज कुमारसामी ने 10 जुलाई 2017 से लेकर 27 अगस्त 2017 के बीच 'गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) और डेटा संग्रह 2017' पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा किया।

ब्लू इकोनॉमी फोरम

ब्लू इकोनॉमी से विकास और स्थायित्व को बढ़ावा

आरआईएस, नई दिल्ली

एफआईटीएम नीतिगत संक्षिप्त

#1 पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंच एवं विस्तार और नवाचारों को प्रोत्साहन द्वारा प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और सुश्री दीपिका यादव

आरआईएस का परिचर्चा पत्र

लॉजिस्टिक्स सुविधा निगरानी तंत्र विकसित करना: व्यापार सुविधा सुधारों के तहत अगला कदम द्वारा राजीव खेर और प्रीतम बनर्जी

आरआईएस डायरी

खंड 13 संख्या 3, जुलाई 2017

आरआईएस संकाय द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. भारत में सतत विकास की ओर , बिबेक देबरॉय और अशोक मलिक (सं.) में *India @ 70 Modi @ 3.5: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत में हो रहे बदलावों को रेखांकित करना,* पीपी: 119–128. विजडम ट्री।

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. ट्रम्प–मोदी बैठक– अर्थव्यवस्था एवं व्यापार में व्यावहारिकता ही सटीक थीम थी, *बिजनेस स्टैंडर्ड,* 04 जुलाई 2017.

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. अफ्रीका से जुड़ाव पर जी20 का विशेष जोर, *जीडीआई–अंतर्राष्ट्रीय विकास ब्लॉग,* 24 जुलाई 2017, जर्मन विकास संस्थान।

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. एशिया अफ्रीका विकास कॉरीडोर का लक्ष्य जन–केंद्रित विकास रणनीति है, *द मिंट,* 18 सितंबर 2017.

डे, प्रबीर और श्रेया पैन. 2017. *'भारत–मंगोलिया आर्थिक संबंध: वर्तमान स्थिति और भावी संभावना', पूर्वोत्तर एशियाई आर्थिक समीक्षा,* खंड 5, संख्या 2.

डे, प्रबीर. 2017. एस्कैप में 'एनटीएम और कृषि निर्यात: परिचय' (सं.) *आसियान के भीतर व्यापार एकीकरण: कंबोडिया, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार और वियतनाम के लिए गैर–टैरिफ उपायों की भूमिका,* बैंकाक।

डे, प्रबीर. 2017. 'लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य में निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले गैर–टैरिफ उपाय: एक आकलन, एस्कैप (सं.) में *आसियान के भीतर व्यापार एकीकरण: कंबोडिया, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार और वियतनाम के लिए गैर–टैरिफ उपायों की भूमिका,* बैंकाक।

डे, प्रबीर और अजित्व रायचौधरी (सं.) 2017. *विश्व के साथ म्यांमार का एकीकरण: चुनौतियां और नीतिगत विकल्प,* पालग्रेव मैकमिलन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर।

डे, प्रबीर. 2017. 'क्षेत्रीय एकीकरण और म्यांमार: वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं' डे, प्रबीर और अजित्व रायचौधरी (सं.) में *विश्व के साथ म्यांमार का एकीकरण: चुनौतियां और नीतिगत विकल्प,* पालग्रेव मैकमिलन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर।

दाश पी. 2017. 'कोरिया की विकास सफलता के बारे में बताना: वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास, एफडीआई और औद्योगिक बराबरी (कैच–अप) की भूमिका।' *मैन एंड डेवलपमेंट,* खंड XXXIX, संख्या 2, पीपी.21–50 (जून 2017).

जेम्स, टी.सी. 2017. *'वैश्वीकरण और भारत की अभिनव प्रणालियां: रचनात्मक विनाश की ओर'* नामक खंड में 'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां और अनुसंधान एवं विकास' महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, जुलाई 2017. आईएसबीएन– 978–93–80419–35–0.

जेम्स, टी.सी. 2017. *'आम स्वास्थ्य चुनौतियां और सहयोग की संभावनाएं'*। ब्रिक्स का एक दशक: भविष्य के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य। डरहम विश्वविद्यालय और विले–ब्लैकवेल, सितंबर, 2017. आईएसबीएन: 978–81–935340–5–2.

जेम्स, टी.सी. 2017. *'भारतीय जेनेरिक फार्मा उद्योग और बौद्धिक संपदा अधिकार' कॉमन कॉज जर्नल* , अप्रैल–जून।

मोहंती, एस.के. 2017 'एसडीजी–14: सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवेज़ टू मैनेज ओशन वेल्थ,'' सैयद मुनीर खुसरो(संपादित) *टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेसन्स फ्रॉम एमडीजी एंड पाथवेज़ फॉर एसडीजीस,* द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी, एडवोकेसी एंड गवर्नेंस(आईपीएजी), बांग्लादेश, अक्टूबर.(सह–लेखक). आईएसबीएन 9789843429254

श्रीनिवास, कृष्णा रवि, 2017. *'भारत में जीएम फसलों के लिए नियामक व्यवस्था' 'विकासशील देशों में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव'* में, एडेमोला ए. एडेन्ले, ई. जेन मॉरिस और डेनिस जे. मर्फी द्वारा संपादित। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2017 पीपी 236–246.

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाष: 91–11–24682177–80
फैक्स: 91–11–24682173–74, ई–मेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: http://www.ris.org.in

Follow us on:
www.facebook.com/risindia
@RIS_NewDelhi
www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादक: तीश मल्होत्रा

एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोरः आगे की राह

Mk- ,l- t;'kdj
विदेश सचिव

एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) के विजन दस्तावेज, जिसे इसी साल मई में अफ्रीकी विकास बैंक की बैठक में जारी किया गया था, में इसकी परिकल्पना 'एक जन–केंद्रित सतत विकास रणनीति' के रूप में की गई है। इसका ब्योरा विस्तृत विचार–विमर्श की प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाएगा जिसमें विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाएगा। मैं इस संदेश को रेखांकित करता हूं क्योंकि विकास और कनेक्टिविटी से जुड़ी पहल सही मायनों में विश्व स्तर पर केवल तभी अपनाई जाती हैं जब वे व्यापक सलाह–मशविरा प्रक्रिया के जरिए उभर कर सामने आती हैं। यह विशेष रूप से तब आवश्यक हो जाता है जब आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस तरह की पहल मांग पर ही आधारित हों और ये स्थानीय स्वामित्व में रहें।

चूंकि हम एएजीसी को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि कॉरिडोर यह प्रतिबिंबित करेगा कि हमारा नजरिया दुनिया के प्रति आखिरकार कैसा है। आज इस क्षेत्र के देशों में काफी हद तक सहमति है और यह उनका साझा दृष्टिकोण ही है जो हमें इस संयुक्त प्रयास में एकजुट कर रहा है। हम स्वाभाविक रूप से सर्वत्र मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, सुशासन, कानून के शासन, खुलेपन, पारदर्शिता और समानता को ध्यान में रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, स्थानीय स्वामित्व की मजबूत भावना अवश्य ही होनी चाहिए और यह केवल आपसी परामर्श से परियोजना की डिजाइनिंग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं कौशल को प्रोत्साहन देने से ही संभव है। वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करना भी अत्यंत जरूरी है, ताकि अनिश्चित ऋण की कोई नौबत न आए। हमारी गतिविधियां अवश्य ही पूरी तरह से सुरक्षा एवं संरक्षण के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और इनके तहत संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का ख्याल रखा जाना चाहिए।

इन व्यापक सिद्धांतों को देखते हुए यह अत्यंत संतोष की बात है कि एएजीसी के ये चार घटक हैंः (1) विकास एवं सहयोग परियोजनाएं (2) गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल (इनपुट) (3) क्षमता एवं कौशल संवर्धन (4) लोगों के बीच साझेदारियां। ये चारों ही घटक पारस्परिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और एक साथ होकर उस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्हें मैंने अभी–अभी समझाया है। दरअसल, विकास सहयोग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को लेकर भारत का जो अपना दृष्टिकोण है उसमें ये सारे ही तत्व बखूबी विद्यमान हैं।

विकास एवं कनेक्टिविटी आज भारत की विदेश नीति के केंद्र में हैं। 'सबका साथ, सबका विकास' दृष्टिकोण अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों और घरेलू स्तर पर हो रहे विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत की विदेश नीति में पहले से ही जोरदार ढंग से परिलक्षित हो रही है जिसमें 'पड़ोसी पहले' को तवज्जो दी जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान यह सुनिश्चित करने में नई ऊर्जा और अतिरिक्त संसाधन लगाए गए हैं कि हमारे निकटतम पड़ोसी देश भी हमारी विकास गाथा से लाभान्वित हों। यह कल नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा के सकारात्मक परिणामों में अवश्य ही परिलक्षित हुआ होगा। वास्तव में अब आप जो समूचे दक्षिण एशिया में देख सकते हैं वह ऊर्जा, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़ी हमारी परिवर्तनकारी पहल हैं। इन सभी के साकार होते ही एक विशाल क्षेत्रीय सहकारी ढांचे के अभ्युदय में इनके योगदान की काफी सराहना होने लगेगी। गौरतलब है कि आज हम इस क्षेत्र में कई अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों या निकायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

भारत के दक्षिण की ओर समुद्री क्षेत्र में हमारे देश की विभिन्न गतिविधियां दरअसल भूमि पर किए गए कार्यकलापों के लिए पूरक साबित हुई हैं। हिंद महासागर की तरफ अपनाए जा रहे एकीकृत दृष्टिकोण ने हमें पूर्वी अफ्रीका के साथ उतने ही ज्यादा परस्पर तरीके से सोचने का अवसर प्रदान किया है जितना कि प्रशांत द्वीप समूह के साथ है। अफ्रीका में हमारा एक प्रमाणित विकास सहयोग रिकॉर्ड है जो सूडान और रवांडा में बिजली परियोजनाओं एवं बांधों से लेकर तंजानिया में जल उपचार या शोधन तथा इथियोपिया में चीनी मिलों तक में नजर आता है। हमारे प्रशिक्षण केंद्र समूचे महाद्वीप में फैले हुए हैं और हमारे देश में वहां से बड़ी संख्या में छात्रों के आने की एक लंबी परंपरा रही है। हम अपने दृष्टिकोण के तहत न केवल लोगों को मछली पकड़ना सिखाते हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न मछलियों की पहचान करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। अतः हमें उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा लक्ष्य तय करने की जरूरत है, जितना हम एक–दूसरे के लिए कर सकते हैं। मेरे विचार में हमें यह भी संदेश देने की जरूरत है कि हम एक–दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं और कम से कम भारत के मामले में तो यह साफ नजर आता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव निर्मित आपदाओं और आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में भारत जो बड़ी तेजी से सटीक कदम उठाता रहा है वह इस बात का गवाह है। हाल के दिनों में यमन, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका में भारत द्वारा जो कुछ भी किया गया उसके उदाहरण आपके सामने हैं। विजन दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि एएजीसी मजबूत एशियाई अर्थव्यवस्था को अफ्रीका की युवा जनसांख्यिकी या आबादी से जोड़ता है जिसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं। अवसरों और चुनौतियों का यह संयोजन इतना बृहत है कि इसके लिए पूरे मन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली में 25 अगस्त 2017 को 'एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोरः आगे की राह' पर आयोजित परामर्श के दौरान दिए गए विशेष भाषण के मुख्य अंश।